VS-119
04-01-2022

अत्यंत महत्वपूर्ण/विधानसभा
विशेष पत्र वाहक/ई–मेल द्वारा

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
9वॉ तल, सी – विंग दिल्ली सचिवालय,
आई. पी इस्टेट,नई दिल्ली–110002.

एफ.53(37)/अता./ ता प्र.सं.119/द्वि.सत्र का चतुर्थ भाग–2022/दिविस/श.वि./1363-65 दिनांकः 01-01-22

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न शाखा),
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,
पुराना सचिवालय, दिल्ली –110054.

विषयः–दिल्ली सातवीं विधानसभा के द्वि.सत्र का चतुर्थ भाग तारांकित /अतारांकित प्र. स. 119 मान्नीय विधायक श्री मोहन सिंह बिष्ट दिनांक 04.01.2022 को सदन की बैठक के सन्दर्भ में ।

महोदया/ महोदय,

आपको उपरोक्त विषय में उद्धत विधानसभा प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियॉ, मान्नीय मंत्री शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित अग्रित कार्यवाही हेतु इस पत्र के साथ भेजी जा रही हैं।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

उप–सचिव (संसदीय शाखा)

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मान्नीय मंत्री शहरी विकास (दिल्ली सरकार) 7वां तल 'ए' विंग, दिल्ली सचिवालय नई दिल्ली ।
2. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियों सहित ।

उप–सचिव (संसदीय शाखा)

Scanned by TapScanner

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री मोहन सिंह बिष्ट

दिनांक : 04.01.2022

विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 119

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	करावल नगर विधान सभा के अंतर्गत कुल कितनी अनाधिकृत कॉलोनी हैं;	करावल नगर विधान सभा के अन्तर्गत 28 अनाधिकृत कॉलोनियॉ है ।
ख	करावल नगर विधानसभा के अंतर्गत अनधिकृत कॉलोनियों में विकास का कोई भी कार्य आज तक न होने के क्या कारण हैं;	शहरी विकास विभाग ने पिछले वित्तीय वर्ष 2020–21 में कार्यकारी संस्था डीएसआईआईडीसी को 289.19 करोड़ रुपये दिये है और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में 307 करोड़ रुपये की मिसिल विचाराधीन है ।
ग	क्या यह भी सत्य है कि करावल नगर विधान सभा की अधिकतर कॉलोनियों के एस्टीमेट शहरी विकास विभाग के पास बजट के लिए लम्बित पड़े हैं; और	शहरी विकास विभाग दिल्ली सरकार ने कार्यकारी संस्था (डीएसआईआईडीसी) को विकास कार्य के लिए एक मुक्त कॉलोनी वार निधि नहीं देता है ।
घ	इन कॉलोनियों को अभी तक बजट न दिये जाने के क्या कारण हैं तथा कितने दिनों में इनका बजट रिलीज कर दिया जायेगा?	शहरी विकास विभाग दिल्ली सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष 2020–21 में डीएसआईआईडीसी (कार्यकारी संस्था) को रुपये 289.19 करोड़ दिए है और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में 307 करोड़ की मिसिल विचाराधीन है ।

Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02